Inland Water Transport

***1171. Shri T. Subramanyam:** Will the Minister of **Transport and Communications** be pleased to state:

(a) whether as a long tem measure, it has been planned to extend the inland water transport canal from Mangalore to Coondapur in Mysore State, and link it with the West coast canal system of Kerala State; and

(b) whether the operation of ferries to transport men and materials and to guard against loss of life and property has been considered?

The Minister of Transport and Communications (Shri Jagjivan Ram): (a) and (b): The required information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Dam on Ajoy River

***1173. Shri Shree Narayan Das:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Central Government's proposal for the constitution of an inter-State board to settle the difference of opinion with Bihar on the question of erecting a dam on the River Ajoy has been given effect to;

(b) if so, the nature of the constitution of the Board; and

(c) whether the Board has commenced its work?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): (a) No; Sir.

(b) and (c): Do not arise.

रिक्शा चालक संस्थाएं

***११७७. श्री धर्मलिगम :** क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिक्शा चालक संस्थायें (रिक्शा पुलर्स सोसाइटीज) बनाने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो एसी एक संस्था मद्रास में स्थापित की जायेगी ।

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(घ) कितनी और कैसी वित्तीय सहायता देने का विचार किया गया ह ?

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) (क) जी हां ।

(ख) मद्रास में एक समिति गठित की गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) केन्द्रीय सरकार निम्न सुविधाएं देगी :—

(१) राज्य सरकारों को उतना ऋण दिया जायेगा जितना कि वे समितियों को रिक्शायें खरीदने के लिये देंगी । इसकी अधिकतम सीमा २०,००० रुपय प्रति समिति होगी ।

(२) राज्य सरकारों को प्रबन्धकीय व्यय के लिये वित्तीय सहायता देने हेतु अनुदान । यह सहायता ३ से ५ वर्षों की अवधि में प्रति समिति ६०० रुपय तक दी जायेगी । यह वित्तीय सहायता राज्य सरकारों के साथ ५०: ५० के आधार पर बांटी जायगी ।

Per Capita Consumption of Electricity in Andhra Pradesh

***1180. Shrimati Vimla Devi:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the *per capita* consumption of electricity in Andhra Pradesh as on 3rd March, 1962; and

(b) the reasons for such low consumption?